

इस्पात क्षेत्र का सिंहावलोकन

वैश्विक परिदृश्य

- कैलेंडर वर्ष 2021 में, वैश्विक कच्चे इस्पात का उत्पादन 1911.9 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गया और कैलेंडर वर्ष 2020 की तुलना में 3.6% की वृद्धि देखी गई।
- विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रैंकिंग के आधार पर चीन 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक (1032.8 एमटी) बना रहा, इसके बाद भारत (118.1 एमटी), जापान (96.3 एमटी) और यूएसए (86.0 एमटी) का स्थान रहा।
- वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की खपत विश्व के लिए 228 किलोग्राम और चीन के लिए 691 किलोग्राम थी। 2020-21 में भारत के लिए यह खपत 70 किग्रा (स्रोत: जेपीसी) थी।

नोट: विश्व इस्पात संघ की रिपोर्ट, आंकड़े अनंतिम।

घरेलू परिदृश्य

- नियंत्रण मुक्त किए जाने के बाद भारतीय इस्पात उद्योग ने पुनरुत्थानशील अर्थव्यवस्था और इस्पात की बढ़ती हुई मांग पर अवलंबित होकर एक नए विकास चरण में प्रवेश किया है।
- उत्पादन में तेजी से वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत 2017 में कच्चे इस्पात के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक की अपनी स्थिति से पिछले तीन वर्षों (2018-2021) के दौरान कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। भारत विश्व में स्पंज आयरन या डीआरआई का सबसे बड़ा उत्पादक भी था और विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रैंकिंग के आधार पर 2021 (अनंतिम) में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तैयार इस्पात उपभोक्ता था।
- भारत जैसे नियंत्रणमुक्त, उदारीकृत आर्थिक/बाजार परिदृश्य में सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की होती है जो नीतिगत दिशा-निर्देशों को निर्धारित करती है और इस्पात क्षेत्र की दक्षता एवं प्रदर्शन में सुधार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु संस्थागत तंत्र/संरचना की स्थापना करती है।
- इस भूमिका में, सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 जारी की है, जिसमें 2030-31 तक मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर भारतीय इस्पात उद्योग के लिए दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापक रोडमैप निर्धारित किया गया है। सरकार ने सरकारी खरीद में घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों को वरीयता प्रदान करने के लिए एक नीति की भी घोषणा की है।
- सरकार ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध-प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी दी है। यह उम्मीद है कि 2026-27 के अंत तक विशेष इस्पात का उत्पादन 42 मिलियन टन हो जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि देश में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के विशेष इस्पात का उत्पादन और खपत होगी, जिसका अन्यथा आयात किया जाता। इसी तरह,

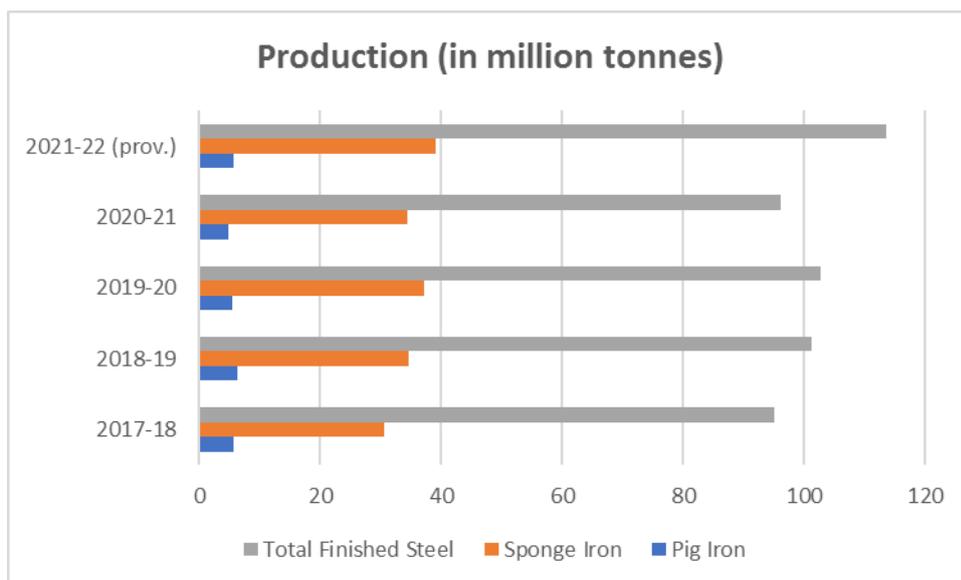
मौजूदा 1.7 मिलियन टन के विशेष इस्पात को मिल रही 33,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की तुलना में विशेष इस्पात का निर्यात लगभग 5.5 मिलियन टन हो जाएगा।

उत्पादन

- इस्पात उद्योग को क्रमशः 1991 और 1992 में लाइसेंसमुक्त और विनियंत्रित कर दिया गया था।
- वर्ष 2021 में भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था।
- वर्ष 2021-22 (अनंतिम) में कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु/स्टेनलेस + गैर मिश्र धातु) का उत्पादन 113.60 एमटी था, जो विगत वर्ष की तुलना में 18.1% की वृद्धि है।
- वर्ष 2021-22 (अनंतिम) में पिग आयरन का उत्पादन 5.76 एमटी था, जो विगत वर्ष की तुलना में 18.1% की वृद्धि।
- वर्ष 2021 में भारत विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक था। वर्ष 2021-22 (अनंतिम) में देश में कुल स्पंज आयरन उत्पादन (39.03 एमटी) का 77% कोयला आधारित मार्ग के कारण था।
- पिग आयरन, स्पंज आयरन और कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु/स्टेनलेस + गैर-मिश्र धातु) के उत्पादन के संबंध में पिछले पांच वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

भारतीय इस्पात उद्योग: उत्पादन (मिलियन टन में)					
श्रेणी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
पिग आयरन	5.73	6.41	5.42	4.88	5.76
स्पंज आयरन	30.51	34.71	37.10	34.38	39.03
कुल तैयार इस्पात	95.01	101.29	102.62	96.20	113.60
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति ; *अनंतिम					

उपर्युक्त तालिका का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण नीचे दिया गया है:-



मांग - उपलब्धता

- देश में लोहे और इस्पात की मांग-उपलब्धता सहित औद्योगिक गत्यात्मकता बड़े पैमाने पर बाजार के कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं और मांग-उपलब्धता में अंतर को ज्यादातर आयात के माध्यम से दूर किया जाता है।
- इस्पात उपभोक्ता परिषद् की बैठक के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ संवाद किया जाता है, जिसका नियमित आधार पर आयोजन किया जाता है।
- संवाद से उपलब्धता की समस्याओं, गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों के निवारण में मदद मिलती है।

इस्पात की कीमतें

- लौह और इस्पात के मूल्य विनियमन को 16.1.1992 को समाप्त कर दिया गया था। तब से इस्पात की कीमतें बाजार के कारकों की परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित होती हैं।
- घरेलू इस्पात की कीमतें अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल की कीमतों में रुझान, बाजार में मांग-आपूर्ति की स्थितियों, अंतरराष्ट्रीय मूल्य रुझानों से प्रभावित होती हैं।
- एक सुविधाप्रदाता के रूप में, सरकार इस्पात बाजार की स्थितियों की निगरानी करती है और अपने आकलन के आधार पर राजकोषीय और अन्य नीतिगत उपायों को अपनाती है।

आयात

- पिछले पाँच वर्षों के लिए कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु/स्टेनलेस + गैर मिश्र धातु) के आयात से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

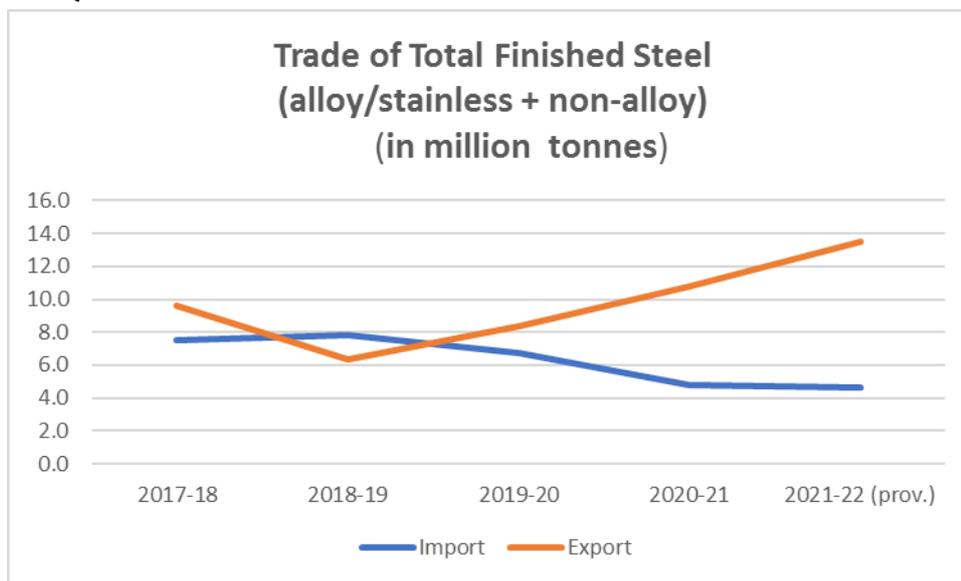
भारतीय इस्पात उद्योग: कुल तैयार इस्पात का आयात (मिलियन टन में)					
श्रेणी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
मात्रा	7.48	7.83	6.77	4.75	4.67
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति ; *अनंतिम					

निर्यात

- विगत पाँच वर्षों के दौरान, भारत 2017-18, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में कुल तैयार इस्पात का निवल निर्यातक था।
- पिछले पाँच वर्षों के लिए कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु/स्टेनलेस + गैर मिश्र धातु) के निर्यात से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

भारतीय इस्पात उद्योग: कुल तैयार इस्पात का निर्यात (मिलियन टन में)					
श्रेणी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
मात्रा	9.62	6.36	8.36	10.78	13.49
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति ; *अनंतिम					

विगत पाँच वर्षों के लिए कुल तैयार इस्पात के व्यापार से संबंधित ग्राफीय प्रस्तुतिकरण नीचे दिया गया है:-



लौह और इस्पात पर लेवी

एसडीएफ लेवी: यह लेवी इस्पात क्षेत्र के आधुनिकीकरण, विस्तार और विकास के वित्तपोषण के लिए शुरू की गई थी। इस निधि से अन्यो के साथ-साथ, एकीकृत इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण, पुनर्वासन, विविधीकरण, नवीकरण और प्रतिस्थापन, अनुसंधान एवं विकास, एसएसआई निगमों को छूट सहित अन्य के लिए पूंजीगत व्यय में मदद दी जाती है। एसडीएफ लेवी 21.4.94 को समाप्त कर दी गई थी। इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है

ईजीईएफएफ: यह लेवी इंजीनियरिंग निर्यातकों के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के मूल्य अंतर लागत की प्रतिपूर्ति के लिए शुरू हुई थी। निधि को 19.2.96 को बंद कर दिया गया।

निजी क्षेत्र में लौह और इस्पात के विकास के अवसर

नई औद्योगिक नीति व्यवस्था

नई औद्योगिक नीति में (क) भारतीय लौह और इस्पात उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटाकर और (ख) अनिवार्य लाइसेंसिंग से छूट देकर इसे निजी निवेश के लिए खोल दिया गया। विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अब स्वचालित मार्ग के तहत कुछ सीमाओं तक स्वतंत्र रूप से अनुमति दी गई है। उदारीकृत परिदृश्य में इस्पात मंत्रालय नए और मौजूदा इस्पात संयंत्रों को व्यापक दिशा-निर्देश और सहायता प्रदान करते हुए एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाता है।

विकास की रूपरेखा

(i) **इस्पात:** औद्योगिक नीति के उदारीकरण और सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों से इस्पात उद्योग में निजी क्षेत्र के प्रवेश, भागीदारी और विकास को सुनिश्चित प्रोत्साहन मिला है। जबकि मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तार किया जा रहा है, वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में आधुनिक, लागत प्रभावी, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित बड़ी संख्या में नए इस्पात संयंत्र भी सामने आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, मांग पक्ष की तीव्र और संतुलित वृद्धि ने घरेलू उद्यमियों को देश के विभिन्न राज्यों में नई ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है।

वर्ष 2021-22 में क्रूड इस्पात की क्षमता 154.23 एमटी (अनंतिम) थी, और भारत, जो विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार, वर्ष 2021 में विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था, के नाम, अनेक तरह के ग्रेडों का उत्पादन करने की क्षमता हैं और वह भी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के।

(ii) **पिग आयरन:** भारत पिग आयरन का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। उदारीकरण के बाद, निजी क्षेत्र में कई इकाइयों की स्थापना के साथ, न केवल आयात में भारी कमी आई है, बल्कि भारत कच्चे

जेपीसी: मई, 2022 में अद्यतित

लोहे का निवल निर्यातक बन गया है। वर्ष 2021-22 (अनंतिम) में देश में पिग आयरन (5.76 एमटी) के कुल उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 89% थी।

(iii) **स्पंज आयरन:** भारत, जो स्पंज आयरन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, में देश के खनिज समृद्ध राज्यों में स्थित अनेक कोयला आधारित इकाइयाँ हैं। विगत वर्षों में, कोयला आधारित मार्ग एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है और 2021-22 (अनंतिम) के दौरान देश में कुल स्पंज आयरन के उत्पादन में 77 प्रतिशत का योगदान रहा है। स्पंज आयरन बनाने का उत्पादन भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है और यह 39.03 मिलियन टन (2021-22) (अनंतिम) रहा है।
